

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या ३५६/XVII-2/2011-01(15)/2010
देहरादून: दिनांक: २५ मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम-33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के उपरान्त प्रदेश में दिनांक 19.01.2011 से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTERGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) लागू हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DISTRICT CHILD PROTECTION OFFICER) नामित किया जाता है। जिन जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारी का पद रिक्त है, उनमें जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदगत दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(एम० एच० खान)
सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या:- ३५६/XVII-2/2011-01(15)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष/प्रधान मंजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी० आर० टम्टा)
अपर सचिव